श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं आनरेबल मेम्बर को यही बताना चाहता हूँ कि 122 मिल्स कानपूर की भी शामिल हैं ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, by the end of March, the Government spent Rs. 11,035 crores for modernising the mills in the private sector as well as Hie public sector. I would like to know us to how many of them are actually working now and what are the number of mills, both in the private sector and the public sector, for which the modernisation fund has been given.

SHRI G. VENKAT SWAMY : The Government sanctioned Rs. 750 crores for modernisation programme and this was allotted to the mills in the private sector as well as in the public sector. A large number of mills have taken this loan. This fund was created in 1st August, 1986. This amount of Rs. 750 crores was disbursed by the Government of India through the IDBI. Altogether, a sum of Rs. 877.94 crores was disbursed for modernisation of the mills.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, I wanted to know as to how many of them are actually working and how many of them are not working even after modernisation,

;

SHRI G. VENKAT SWAMY : As I mentioned, around Rs. 877 crores were allocated for modernisation of the textile mills and all the mills are operating now.

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे : मैडम, एन० टी० सी० में एक तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, बी० आई० एफ० आर० में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर हर स्टेट में स्टेट्स के कन्सर्न होते हैं । जब भी रिनोवेशन और माडर्नाइजेशन की स्कीम एप्रूव कर देते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार माडर्नाइजेशन हो गया तो ये मालिक लोग कामर्शियलाइज करते है और कामर्शियलाइज करके वहां की जो प्रापर्टी है वह बेचने का उनका प्रयास होता है । सभी उसी तरह से फिर दिवाला निकालते हैं और फिर दुबारा वह प्रापर्टी या वह मिल लास में आती है । इसलिए क्या आपके पास ऐसी कोई मानीटरिंग एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, एन० टी० सी० की और फाइनेंस की, इतना ही मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : ऐसी कोई स्कीम प्राइवेट सेक्टर के माडर्नाइजेशन के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में तो नहीं है । आलरेडी एन० टी० सी० मिल्स को हमने लिया है, जिसको ट्रिपारटाइट कमेटी ने एप्रूव किया । उसको हम कैबिनेट नोट बनाने के बाद टेक्सटाइल, एन० टी० सी० मिल्स के लिए जायेंगे । मगर प्रायवेट मिल्स के माडर्नाइजेशन के लिए जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम 750 करोड़ रुपीज हमने रखा था । वह जो हुआ है उसमें वे सारी की सारी अच्छी चल रही है । रहा यह कि चंद लोग, प्रायवेट मिल ओनर्स–और असल क्वेश्चन हमारे शिन्दे जी का यही है कि वे माडर्नाइजेशन के नाम पर प्रापर्टीज को, सरप्लस लैंड को बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कोई कानून नहीं है । मगर स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है ।

Doordarshan Kendra at Bhubaneswar

*324. SHRI SARDA MOHANTY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bhubaneswar, the Capital of Orissa, is the only State Capital in the country having no Dooardarshan Kendra; and

(b) if so, by when Government of India porpose to instal Doordarshan Kendra at Bhubaneswar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir. A Doordarshan Kendra is operating at Bhubaneswar Since 19-11-1992.

(b) Does not arise.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question your is over.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**यू० एन० ट्रस्ट फंड के लिए सहायता**

*श्री राम गोपाल यादव :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० ट्रस्ट फंड के अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं को काम देने हेतु केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता की मांग की है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से काम देने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**राज सहायता समाप्त करना अथवा उसमें कमी करना**

*326. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न वस्तुओं पर दी जाने वाली राज-सहायता समाप्त करने अथवा उसमें कमी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी वस्तुओं पर राज-सहायता समाप्त की जाने वाली है अथवा उसमें कमी की जाने वाली है; और

(ग) राज-सहायता समाप्त होने अथवा कम होने की स्थिति में आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता को कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन पर राजकोषीय संतुलन के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राज-सहायता बिल को अपने राजकोषीय साधनों की सीमा के अन्तर्गत रखा जाए । फिर भी, राज-सहायताओं को नियंत्रित करते हुए, सरकार की यह नीति रही है कि गरीबों और जरूरतमन्द लोगों के हितों की रक्षा की जाए ।

**Fuel crunch in Tata Electric Company**

*327. SHRI VIREN J. SHAH :

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Business Pioneer of 25th March, 1994 under the caption, 'Fuel crunch forces TEC to half power output';

(b).jf so, whether it is a fact that the Oil and Natural Gas Commission is supplying about 0.2 to 0.3 million cubic metres of gas per day. to Tata * Electric Company against their committed l.5 million cubic metres per day ;

(c) if so, what are the reasons and facts in this regard;

(d) whether it is a fact that TEC has almost exhausted its stocks of fuel and are likely to shut down one of its 500 MW units, affecting electric supply to many parts of Mumbai city;

(e) to what extent the short supply of gas to TEC has affected the industrial production and day-to-day life of the people in Mumbai; and

(f) what steps the Ministry of Petro leum and ONGC have taken so far to meet the requirements of TEC?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. The position of availability of gas to various users is kept under constant review by the Ministry of Petroleum & Natural Gas. For 1993-94, a commitment of supply of 0.5 MCMD was made for the Trombay Thermal Power Station of M/s Tata Electric Company (TEC) as against which the average supply of gas during the same period has been 1.16 MCMD.

(d) and (f) This station is designed as a mullifuel station and LSHS, which is the alternate fuel, could be imported freely being a decanalised item by M/s TEC. The Ministry of Petroleum & Natural Gas has planned a minimum supply of 50,000 tonnes per month of LSHS to M/s TEC. M/s TEC would need to import any LSHS in excess of 50,000 tonnes per month, as per requirement. The Oil companies would extend the necessary help in the matter.

(e) The Maharashtra State Electricity Board from time to time provides additional supplies of electricity keeping Mumbai's requirement in mind.

**लम्बे रेशे वाली रूई का आयात**

*328. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे रेशे की बढ़िया किस्म की रूई के आयात का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और